# राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

**वर्ष 11 अंक 1** **जनवरी–जून 2009**

**1.''वृद्धावस्था एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण''**–प्रोफेसर जे.पी. पचौरी, अध्यक्ष समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर–गढ़वाल (उत्तराखण्ड),डा. जे.पी. भट्ट, प्रवक्ता समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर–गढ़वाल, सुषमा नयाल, शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर–गढ़वाल (उत्तराखण्ड)।

प्रस्तुत शोध पत्र उत्तराखण्ड के जनपद पौड़ी मे स्थित श्रीनगर शहर के वृद्धजनों पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्यों का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र के अंतर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वृद्धजनों की विभिन्न सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, समस्याओं का वैज्ञानिक विवरण एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया हैं।

**2.''राज्य प्रायोजित आतंकवाद के सन्दर्भ में मैकियावेली और कौटिल्य की अवधारणा – एक तुलनात्मक विवेचना''**–डॉ. स्वस्ति चौधरी,विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, जे.डी. वीमेन्स कालेज, मगध विश्वविद्यालय, पटना (बिहार), डा. बिहारी लाल चौधरी,व्याख्याता स्नातकोत्तर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, तिलका माझी विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)

आतंकवाद एक ऐसे तरीके अथवा विधि को कहा जाता है जिसमें कोई संगठित समूह योजनाबद्ध रूप से हिंसात्मक क्रियाओं के प्रयोग से किसी व्यक्ति, समुदाय या उसके एक बड़े भाग को भयभीत कर वांछित उद्देश्य को प्राप्त करता है। आतंकवाद का प्रयोग सत्ता के एक उपकरण के रूप में भी किया जाता है। राजतंत्र द्वारा अपनाए गए हिंसात्मक व्यवहार की परम्परा इतिहास की जड़ों में दिखाई देती है। प्रस्तुत लेख राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के संदर्भ में मैकियावेली और कौटिल्य की अवधारणा के तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित है।

3.**''विश्वविद्यालय स्वायत्तता : क्षेत्र एवं चुनौतियां''**–डॉ. (श्रीमती) कीर्ति राजिमवाले,सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, (राजस्थान)

विश्वविद्यालय स्वायत्तता शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शैक्षिक और प्रशासनिक निर्णय लेने में विश्वविद्यालयों को मिली स्वतन्त्रता है। लेकिन व्यवहार में एक ओर विश्वविद्यालयेत्तर ऐजन्सियाँ वित्त, प्रवेश और नियुक्ति सम्बन्धी नियमों आदि के माध्यम से स्वायत्तता को नियन्त्रित करने में भूमिका निभाती हैं और दूसरी ओर आंतरिक परिस्थितियाँ, जिसमें नौकरशाही और कारपोरेट संस्कृति का बढ़ता हुआ प्रभाव और विश्वविद्यालय के सदस्यों की स्वहित प्रधानता और अहमवाद आदि को सम्मिलित किया जा सकता है, ऐसा वातावरण बनाती हैं जिसमें बाह्य एजेन्सियों को हस्तक्षेप करने और स्वायत्तता को सीमित करने का अवसर मिल जाता है। प्रस्तुत लेख इसी स्थिति को प्रकाशित करने का एक प्रयास है।

4.**''आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में बदलते उपभोग के प्रतिमानः शिक्षित युवजनों के विशेष संदर्भ में''**–डॉ. यू.बी. सिंह,रीडर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग फीरोज गांधी कालेज, रायबरेली (उ.प्र.), कृष्ण कुमार, शोध अध्येता समाजशास्त्र विभाग फीरोज गांधी कालेज, रायबरेली (उ.प्र.)

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तार्किक और वैज्ञानिक विश्वदृष्टि, आर्थिक वृद्धि तथा विज्ञान और तकनीकी के अधिकाधिक उपयोग पर आधारित है। आज यह प्रक्रिया पूरे विश्व में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। भारत के संदर्भ में देखने पर इसका प्रभाव सभी वर्गों पर दिखाई पड़ता है किन्तु इससे सर्वाधिक प्रभावित है

युवा वर्ग। प्रस्तुत लेख में शिक्षित युवावर्ग में आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में बदलते उपभोग प्रतिमानों को प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है।

**5.''ग्रामीण–नगरीय प्रवसन : एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन''**–डॉ. उदयवीर सिंह, रीडर, समाजशास्त्र विभाग, कर्मक्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा, डॉ. मधु, प्रवक्ता, समाजशास्त्र, कर्मक्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा(उ.प्र.)

सामान्यतः किसी व्यक्ति अथवा परिवार के द्वारा रोजी–रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन को प्रवसन कहते हैं। प्रवसन प्रमुखतः जनसंख्या वृद्धि तथा रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता का परिणाम होता है। प्रस्तुत लेख ग्रामीण–नगरीय प्रवसन अर्थात गाँव से नगर की ओर प्रवसन, जो वर्तमान भारत की एक गंभीर समस्या है, की स्थिति, कारणों एवं सुझावों को प्रकटित करता है।

**6.''रतौंधी की सामाजिक औषधि(बिहार का एक अध्ययन)''**–डॉ. अलख निरंजन सिंह, विभागाध्यक्ष,समाजशास्त्र विभाग, एस.एन.एस.आर.के.एस. कालेज सहरसा (बिहार),डॉ. अनिल वर्मा,पी.एच.डी. मानवशास्त्र विभाग, महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मैमोरियल कालेज, दरभंगा, (बिहार), डॉ कुमुद कुमारी,पी.एच.डी. गृह विज्ञान राजेन्द्र नगर, पटना (बिहार)

रतौंधी पीड़ित बच्चों का स्वास्थ्य गम्भीर चिंता का विषय होता है। इन बच्चों का स्वास्थ्य इतना लड़खड़ाया हुआ हो सकता है कि इनकी मौत हो सकती है। अतः बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए कदमों को सतर्कतापूर्वक उठाने की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध–पत्र में बताया गया है कि मात्र रासायनिक औषधि से रतौंधी का सामना करना पर्याप्त वैज्ञानिक कदम नहीं है। इस बीमारी के सामाजिक कारकों को भी दूर करना आवश्यक है।

**7.''असमान राष्ट्रीय विकास की समस्या तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की स्थिति''**–डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह,उपाचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी(उ.प्र.)।

किसी भी देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार घटित होना चाहिए जिससे इसका लाभ देश के प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। प्रत्येक देश में भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से क्षेत्रीय विषमता पहले से ही विद्यमान होती है तथा समय अंतराल में यह विषमता उतरोत्तर बढ़ती जाती है। भारतीय आर्थिक नीतियों के अंतर्गत यह घोषणा की गई थी कि ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे क्षेत्रीय विषमता कम होगी। किन्तु यथार्थ स्थिति के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत प्रपत्र में उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया का कार्य निष्पादन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा महाराष्ट्र जैसे अग्रगणी राज्यों की तुलना में कैसा रहा है, यह जानने का प्रयास किया गया है।

**8.''मुस्लिम युवाओं के परिवर्ती वैवाहिक दृष्टिकोण''**–डॉ. एच.एन. सिंह, रीडर, समाजशास्त्र विभाग, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़ (उ.प्र.)।

शिक्षा सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रमुख उपकरण है। शिक्षा ने भारतीय जनमानस के वैयक्तिक मूल्य, मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। मुस्लिम समाज भी शिक्षा के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। प्रस्तुत शोध प्रपत्र के अन्तर्गत यह अध्ययन किया गया है कि मुस्लिम युवाओं के विवाह के विभिन्न पक्षों के प्रति दृष्टिकोण क्या है तथा शिक्षा के स्तर की वृद्धि से उनके दृष्टिकोण किस सीमा तक प्रभावित रहे हो हैं?

**9.''जनसंचार माध्यमों के सामाजिक उत्तरदायित्व''**–डॉ. रश्मि त्रिवेदी, रीडर एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग आर.बी.डी. स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय बिजनौर (उ.प्र.)

जन संचार माध्यम जहाँ एक ओर समाज की सोच को अभिव्यक्त करते हैं वही दूसरी ओर जनमत को प्रभावित भी करते हैं। यही कारण है कि आधुनिक समाज जनसंचार माध्यमों पर बहुत अधिक आश्रित होता जा रहा है। अतः इन माध्यमों का सामाजिक दायित्व भी बढ़ता जा रहा है। प्रस्तुत लेख जनसंचार माध्यमों के सामाजिक उत्तरदायित्व का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

**10.''वाराणसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता''**—डॉ. रीता अग्रवाल, रीडर शिक्षाशास्त्र, श्री अग्रसेन कन्या स्वायत्ताशासी पी.जी. कॉलेज, वाराणसी, डॉ. अनीता अग्रवाल, वरिष्ठ प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र, आर्य महिला डिग्री कालेज, वाराणसी (उ.प्र.)

राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति का एक ऐसा राजनैतिक कृत्य है जिससे राजनैतिक पद धारकों का चयन व उसकी निर्णयकारिता प्रभावित होती है। वर्तमान प्रजातन्त्र के युग में जन सहभागिता निश्चित रूप से बढ़ी है। जनसत्ता को व्यवहारिक बनाने का मात्र साधन जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन है। अतः मतदान राजनीतिक सहभागिता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस प्रकार जनता द्वारा शासन तंत्र की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने को ही राजनीतिक सहभागिता का नाम दिया गया है। लोकतंत्र की सफलता का आकलन राजनीतिक सहभागिता की मात्रा के आधार पर किया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में वाराणसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप का विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

**11.''ग्राम पंचायत में निर्वाचित महिला प्रधानों की राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता''**—डॉ. अन्जू रानी, रीडर, समाजशास्त्र विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव न.नि.म. महाविद्यालय, कानपुर, आर.के. सचान,उप कुलसचिव, आई.आई.टी., कानपुर (उ.प्र.)

स्वतंत्रता एवं समानता की आधारशिला पर प्रतिष्ठित भारतीय संविधान ने महिलाओं को जीवन के समस्त क्षेत्रों में पुरूषों के समान ही अधिकार प्रदान किये हैं। राजनीतिक क्षेत्रों मे उनकी भागेदारी सुनिश्चित करने हेतु संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों में विभिन्न स्तरों पर उनके लिए एक तिहाई पद आरक्षित कर दिये हैं। प्रस्तुत लेख ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रधानों की राजनीतिक सहभागिता के मूल्यांकन का एक प्रयास है।

**12.''जैन अल्पसंख्यक, सम्भावित खतरे और समाधान''**—डॉ. मधु अग्रवाल, रीडर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, आर.बी.डी.गर्ल्स कालेज, बिजनौर (उ.प्र.)

हिन्दू धर्म के कतिपय कर्मकाण्डों के विरूद्ध जन्में जैनादि धर्मों को लेकर अक्सर ऊहापोह की स्थिति रही है। ये हिन्दू हैं अथवा हिन्दू धर्म का हिस्सा हैं आदि विवाद भी उपजे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जैन समुदाय को न केवल अलग धार्मिक ईकाई के रूप में मान्य प्रदान की है अपितु जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में संविधान में प्रदत्त समस्त अधिकार भी प्रदान किए हैं। प्रस्तुत लेख में यह प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है कि क्या ऐसे वैधानिक निर्णय राष्ट्र के हित में हैं अथवा इनसे भविष्य में खतरे पैदा होने की संभावनाएं हैं, क्या ये देश में अमन—शान्ति कायम करने में सहायक होगें अथवा हिंसा एवं अशान्ति को बढ़ावा देंगे।

**13''वृद्धों की सामाजिक स्थिति एवं समस्याएं(एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)''**—डॉ. मीना शुक्ला,रीडर, समाजशास्त्र विभाग, वी.एम.एल.जी. स्नातकोत्तर कालेज, गाजियाबाद, डॉ. अनीता गुप्ता, रीडर अंग्रेजी विभाग, बी.एम.एल.जी. स्नातकोत्तर कालेज, गाजियाबाद (उ.प्र.)

भारतीय समाज के वर्तमान अनुमानित आंकड़े संकेत देते हैं कि भारत एक ओर वृद्धों का देश बनता जा रहा है और दूसरी ओर समाज में आ रहे तीव्र परिवर्तनों के कारण परिवार में वृद्धों की देख—देख करने की क्षमता घटती जा रही है। वे भारतीय मूल्य शिथिल पड़ते जा रहे हैं जो वृद्धों की देखभाल का समर्थन

करते हैं।प्रस्तुत लेख वर्तमान भारतीय समाज में वृद्धों की स्थिति तथा समस्याओं को आलोकित करने का एक प्रयास कहा जा सकता है।

**14.''वाल्मीकि रामायण में ईश्वर की अवधारणा : सैधान्तिक विश्लेषण''**—डॉ. रेखा रानी शर्मा, प्रवाचक, संस्कृत विभाग, आर.बी.एस. कॉलिज आगरा।

वाल्मीकि रामायण न केवल भारतीय प्रत्युत विश्व साहित्य में आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। इसने लोगों को आचार—विचार, व्यवहार एवं संस्कार तथा भक्ति एवं भावना की दृष्टि से इतना अधिक प्रभावित किया है कि आज यह काव्य से अधिक धर्म ग्रन्थ बन गया है। इसमें भारतीय जीवन का सर्वांगीण आदर्शपूर्ण एवं ग्राह्य चित्रण है। प्रस्तुत लेख वाल्मीकि रामायण में ईश्वर की अवधारणा को प्रकाशित करने का एक प्रयास है।

**15.''एड्स के प्रति जागरूकता— एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''**—डॉ. दीपाली सक्सेना,प्रवक्ता समाजशास्त्र, डी.जी. कालेज, कानपुर (उ.प्र.)

समकालीन विश्व में विशेषकर पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, उपभोक्तावाद, यौन उन्मुक्तता, भारतीय मूल्यों की उपेक्षा, नैतिक शिक्षा का अभाव और सबसे बढ़कर भोगवादी संस्कृति में एक अत्यंत ही गम्भीर समस्या का जन्म और विकास हुआ है जिसे एड्स के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र मे एड्स क्या है, इसके प्रसार के स्त्रोत एवं कारण तथा जन सामान्य में एड्स के प्रति जागरूकता को विभिन्न आधारों पर समाजशास्त्रीय रूप से विश्लेषित किया गया है।

**16.''भारत में महिलाओं की स्थिति और उससे संबंधित सामाजिक विधानों का क्रियान्वयन एवं प्रभाव''**—डॉ. ऊषा कुशवाह,सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, जी.एल.एस. महाविद्यालय, मानमौर, जिला मुरैना (म.प्र.), डॉ. एस.एस. भदौरिया, से.नि. प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र, एम.एल.बी., शासकीय स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, गवालियर(म.प्र.), डॉ. मोनिका सिंह भदौरिया, मेडिको सोशल वर्कर, गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

**17.''महिला उत्थान एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी''**—डॉ. धनंजय सहाय, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, श्री अग्रसेन कन्या पी.जी. कालेज, परमानन्दपुर, वाराणसी (उ.प्र.)

महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को आजकल काफी जोर—शोर से उठाया जा रहा है ऐसी स्थिति में यदि महात्मा गांधी के विचारों पर अमल किया जाये तो हमें महिलाओं की स्थिति में त्वरित गुणोत्तर सुधार नजर आयेगा। बापू ने एक तरफ जहां बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं दहेज प्रथा का पुरजोर विरोध किया वहीं दूसरी तरफ विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा का वे जोरदार समर्थन करते थे। प्रस्तुत लेख महिला उत्थान के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों को प्रस्तुत करता है।

**18.''भारतीय राजनीति और जाति''**—डा. संदीप चतुर्वेदी, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

जाति प्रथा हिन्दू सामाजिक व्यवस्था की केन्द्रीय संस्था रही है। स्वाधीनोत्तर भारत में संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों के स्थापित होने के बाद भी भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव अनवरत रूप से बढ़ता ही जा रहा है।सामाजिक क्षेत्र में जहां एक ओर जाति की पकड़ कमजोर हुई है वहीं राजनीति में जाति अपनी निर्णायक भूमिका निभा रही है। प्रस्तुत लेख इसी स्थिति को उजागर करने का एक प्रयास है।

**19.''नगरीय कुटीर विनिर्माण उद्यमों में रोजगार, मजदूरी और आय अर्जन(उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर के जरी विनिर्माण उद्यमों का एक सूक्ष्म अध्ययन)''**—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह,उपाचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी,श्री अशोक कुमार मौर्य शोध अध्येता, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.)।

भारत का सूक्ष्म उघोग गांवों, कस्बों और शहरी अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग रहा है। किन्तु क्या भूमण्डलीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के वर्तमान दौर में ये उद्योग अपने को जीवन क्षम या विकास क्षम बना सकेंगे, प्रतियोगात्मक बाजार को टक्कर दे सकेंगे, उन्नत हो रही प्रौद्योगिकी से अपने आपको उबार सकेंगे, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के प्रयासों पर आधारित है प्रस्तुत लेख।

**20.''प्राथमिक शिक्षा का सामाजिक एवं विकासात्मक परिप्रेक्ष्य''**—डॉ. राकेश कुमार आजाद,प्रवक्ता शिक्षा संकाय, बरेली कालेज, बरेली, उ.प्र., श्रीमती रश्मि,शोध अध्येत्री समाजशास्त्र विभाग बरेली कालेज, बरेली, (उ. प्र.)

''समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उसकी क्षमतानुसार स्वतन्त्रतापूर्वक विकास करने की सुविधा प्राप्त हो इसके लिए उसे शिक्षा प्राप्त करना अत्यावश्यक है। आज के युग में मनुष्य के लिए शिक्षा एक 'आवश्यकता' के रूप में उभर कर सामने आयी है। प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की स्थिति, विकास एवं अन्य प्रमुख पहलुओं से सम्बन्ध रखता हैं।''

**21.''विदेशों में भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन (1905—1919) प्रात्वादी आचार्य के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन''**—डॉ. दलजीत सिंह,गाँव एवं डाकखाना रजाथल, जिला हिसार (हरियाणा),डॉ. सरिता देवी,प्राध्यापक, इतिहास विभाग, सैनी डिग्री कालेज, रोहतक (हरियाणा)

भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रारंभ 1905 के बंगाल विभाजन से माना जा सकता है। भारतीय देशभक्तों ने जहां क्रान्तिकारी गतिविधियों का कार्यान्वयन भारत में प्रारंभ किया वहीं भारतीय प्रशासन की जनविरोधी नीतियों का व्यापक स्तर पर पर्दाफाश करके साम्राज्य विरोधी शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने एवं विश्व जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए विदेशों में भी क्रान्तिकारी कार्यक्रम चलाये। इस संदर्भ में प्रात्वादी आचार्य का योगदान भी अतिशय उल्लेखनीय है। प्रस्तुत लेख इसी के विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण का एक प्रयास है।

**22.''घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एवं महिलाएं''**—डॉ. श्वेता सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग श्री अग्रसेन कन्या स्वायत्तशासी पी.जी. कालेज, वाराणसी, डॉ. भावना,प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग श्री अग्रसेन कन्या स्वायत्तशासी पी.जी. कालेज, वाराणसी (उ.प्र.)।

भारतीय समाज में महिलाएँ एक लम्बे समय से सामाजिक तथा घरेलू शोषण एवं हिंसा का शिकार हो रही हैं। घरेलू हिंसा रोकने तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में 'घरेलू हिंसा अधिनियम 2005' एक अतिशय महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है जिससे सम्पूर्ण महिला वर्ग लाभान्वित हो सकेगा। प्रस्तुत लेख महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में इस अधिनियम का मूल्यांकन करने का एक प्रयास है।

**23.''उत्तराखण्ड के मंदिरों की वास्तुकला—एक विवेचना''**—डॉ. जगमोहन भटनागर,विजिटिंग प्रवक्ता देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

प्राचीन काल से एक धार्मिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण उत्तराखण्ड की संस्कृति को अलग पहचान दिलाने में मंदिरों का विशेष योगदान रहा है। अनेक राजाओं ने अनेक स्थानों पर भव्य तथा कलात्मक मंदिर बनवाये। अतः यहां की भूमि में स्थान—स्थान पर मंदिरों के अचानक ही दर्शन हो जाते हैं। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत उत्तराखण्ड के मंदिरों की वास्तुकला का विवेचन किया गया है।

**24.''ग्रामीण समाज में शैक्षिक विकास की सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ''**–आलोक कुमार यादव,प्रवक्ता एवं शोध अध्येता विवेकानन्द ग्रामोद्योग महाविद्यालय, दिबियापुर–औरैया (उ.प्र.)

वैश्विक स्तर पर विद्यमान आधारभूत मानवअधिकारों से सम्बन्धित समस्याओं में शैक्षिक अविकास की समस्या सर्वाधिक ज्वलंत एवं ध्यानाकर्षक है क्योंकि शिक्षा जहां समाज में समृद्धि और विकास की वाहक है वहीं समाज के सर्वांगीण विकास की पूर्व आवश्यकता भी है। प्रस्तुत लेख भारतीय ग्रामीण समाज में शैक्षिक विकास की सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाओं पर प्रकाश डालता है।

**25.''अठारहवीं सदी में राजनीतिक–आर्थिक स्थिति और राज्य निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन''**–डॉ. दलजीत सिंह,गाँव एवं डाकखाना रजाथल, जिला हिसार (हरियाणा)

अठारहवीं सदी के भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी थी और राज्य निर्माण संभव था या नहीं। यह वाद–विवाद वास्तव में अंग्रेजी काल में ही प्रारम्भ हो गया था। साम्राजयवादी इतिहासकार जैसे जेम्स मिल डूस्किन, हैनरी बेवरिज आदि ने भारत में 18वीं सदी के युग को अंधकार का युग माना है। भारत के कुछ राष्ट्रवादी विद्वान जैसे सर जदुनाथ सरकार एवं ताराचंद भी इस विचार से सहमत थे। प्रस्तुत लेख में अठारहवीं सदी के भारत में राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर कितना विकास हुआ और कितना अंधकारमय युग था एवं राज्य निर्माण की प्रक्रिया कैसी रही का विश्लेषण किया गया है।

**26.''अनुसूचित जातीय युवकों की धार्मिक आकांक्षाएं''**–राम लला वर्मा,शोध अध्येता समाजशास्त्र, राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुलतानपुर (उ.प्र.)

मानव जीवन एवं समाज में धर्म का स्थान अतिशय महत्वपूर्ण रहा है। आधुनिकीकरण की तीव्र प्रक्रिया के परिणामस्वरूप यद्यपि सांप्रत भारत में धर्म के महत्व एवं प्रभाव में कुछ कमी अवश्य देखी जा सकती है किन्तु जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से मनुष्य का सम्बन्ध समाप्त होना संभव नहीं है। प्रस्तुत लेख सांप्रतिक भारतीय समाज में अनुसूचित जातीय युवाओं की धार्मिक आकांक्षाओं को उजागर करने का एक प्रयास है।

**27.''ग्रामीण स्वास्थ्य संरक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव''**–दीपिका श्रीवास्तव,समाजशास्त्र विभाग, दयानंद गर्ल्स (पी.जी.) कालेज, कानपुर (उ.प्र.)

स्वास्थ्य की अवधारणा स्थिर अवधारणा न होकर एक गतिशील अवधारणा है। स्वास्थ्य के द्वारा न केवल मानवीय सुख की वृद्धि होती है, वरन् समुदाय की उत्पादन शक्ति एवं कार्यकुशलता, क्षमता, उत्पादकता में भी अभिवृद्धि होती है। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए भी यह आवश्यक है कि राष्ट्र के सदस्यों का स्वास्थ्य स्तर उन्नत हो। प्रस्तुत लेख ग्रामीण स्वास्थ्य संरक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं की महत्ता एवं उनके प्रभावों का उल्लेख करता है।

**28.''सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के जीवन में प्रतिकूलता''**–कैलाश चन्द्र,प्रवक्ता, सा.ध.बा.वि. राम इंटर कालेज, पीलीभीत (उ.प्र.)

सेवा निवृत्ति के बाद लोगों की मानसिकता एवं स्वयं की सामाजिक प्रस्थिति पर सामान्यतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे अनेकानेक स्थापित मूल्यों एवं विश्वासों के प्रति बुजुर्गों में उदासीनता बढ़ती है जिसके कारण वे समाज की मुख्य धारा से अपने आप को अलग पाते हैं। वे अपने को आर्थिक रूप से कम संतुलित महसूस करते है एवं उनका सामाजिक समायोजन भी एक समस्या सा प्रतीत होता है। प्रस्तुत लेख इसी समस्या को प्रकाशित करने का एक प्रयास है।

**29.''आदिवासियों के सामाजिक जीवन के विविध पक्ष(सोनभद्र जनपद के दुद्धी तहसील के आदिवासियों पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)''**–चन्द्रशेखर सिंह,शोध अध्येता, समाजशास्त्र विभाग, जगतपुर पी.जी. कालेज, जगतपुर, वाराणसी (उ.प्र.) ।

साँस्कृतिक संवर्द्धन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आदिवासी समाज में विकासवादी परिवर्तन का प्रसार उत्रोत्तर हो रहा है। परन्तु आदिवासी और गैर आदिवासी संस्कृति के परस्पर सम्पर्क के कारण संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है जिसके कारण विविध प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही हैं। प्रस्तुत लेख इसी स्थिति को प्रकाशित करने का एक प्रयास रहा है।

**30.''बुनकर मुस्लिम बाल–श्रमिकों के शोषण का स्वरूप''**–अब्दुल हसन,शोध अध्येता, समाजशास्त्र विभाग, अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर स्वायत्तशासी महाविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.) ।

विश्व में साधारणतया तीसरीं दुनिया के देश बाल–श्रम को एक सामाजिक–आर्थिक बुराई के रूप में स्थापित करते हैं तथा बाल श्रमिकों को अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश करते हैं। प्रस्तुत लेख बुनकर व्यवसाय के अंतर्गत बाल–श्रमिकों के शोषण की स्थिति को उजागर करने का एक प्रयास है।

**31.''प्राचीन भारतीय समाज में अर्थ का महत्व''**–अनिल यादव,शोध अध्येता, इतिहास विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)।

महाभारत में कहा गया है कि जैसे पर्वतों से बहुत सी नदियाँ बहती हैं उसी प्रकार संचित घन से समस्त प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान होता रहता है। वास्तव में मानव जीवन में धन अथवा अर्थ अतिशय आवश्यक है। प्रस्तुत लेख में प्राचीन भारतीय समाज में अर्थ की महत्ता को प्रकाशित किया गया है।

**32.''हिन्दू और मुस्लिम समुदायों में शिशुओं की पोषण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन''**–शीतल शर्मा,शोध अध्येत्री गृह विज्ञान, एन.के.बी.एम.जी. पी.जी. कालीज, चन्दौसी (मुरादाबाद), डॉ. बी.डी. हरपलानी, विभागाध्यक्षा गृह विज्ञान एवं प्राचार्या एस0बी0डी0 महिला महाविद्यालय, धामपुर बिजनौर (उ.प्र.)

भारत अनेक समुदायों, धर्मों एवं संस्कृतियों का देश है जहां खान–पान, रहन–सहन एवं जीवन शैली में विविधता देखने को मिलती है। विभिन्न समुदायों में पोषण की विधियों की अवस्थाओं में दृष्टिगोचर होती है। प्रस्तुत लेख हिन्दू और मुस्लिम समुदायों में शिशुओं की पोषण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करने का एक प्रयास रहा है।

**33.''आतंकवाद : जेहाद एवं शहादत का समाजशास्त्र''**–डा. अरूण कुमार सिंह, जिला सहकारी बैंक, मेरठ (उ.प्र.)

वर्तमान समय में आतंकवाद विश्व के कोने–कोने में फैला हुआ है। आतंकवादी घटनाओं को एक धर्म विशेष से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां इसे जेहाद अथवा शहादत की संज्ञा दी जा रही है। प्रस्तुत लेख इन अवधारणाओं की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने का एक प्रयास कहा जा सकता है।

**34.''मलिन बस्तियों की समाजार्थिक समस्याएं एवं 'डूडा' कार्यक्रमों का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन''**–डा. सुधीर कुमार श्रीवास्तव,प्रवक्ता, समाजशास्त्र विभाग, रामजी सहाय पी.जी. कालेज, रूद्रपुर, देवरिया (उ.प्र.)

मलिन बस्तियों के निवासियों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाये जाते हैं। प्रस्तुत लेख आजमगढ़ जनपद में मलिन बस्तियों के निवासियों की समाजार्थिक समस्याओं को सुधारने में डूडा के कार्यक्रमों के मूल्यांकन के प्रयास पर आधारित है।

**35.''परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का परिवार नियोजन पर प्रभाव''**–रश्मि चतुर्वेदी,शोध अध्येत्री गृह विज्ञान, एन.के.जी.एम.जी. (पी.जी.) कालेज, चन्दौसी (मुरादाबाद), डॉ. बी.डी.

हरपलानी, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग एवं प्राचार्य एस.बी.डी. महिला महाविद्यालय, धामपुर बिजनौर (उ.प्र. )

स्वतत्रंता प्राप्ति के छः दशक बाद भी देश में परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव के फलस्वरूप भारत अच्छे स्वास्थ्य के लक्ष्य से बहुत दूर है। कम आयु में विवाह भी अच्छे स्वास्थ्य में बहुत बड़ी बाधा है। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत विवाह के समय लड़की की आयु तथा परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का परिवार नियोजन पर प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

**36.''महिला सशक्तिकरण एवं प्रजनक अधिकारः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण''**—उमा भण्डारी,शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, श्री अग्रसेन कन्या स्वायत्तशाली पी.जी. कालेज, परमानन्दपुर, शिवपुर, वाराणसी (उ.प्र.) ।

सामान्यत महिलाओं के सशक्तिकरण का विश्लेषण एवं मूल्यांकन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संदर्भों में किया जाता है। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रजनक स्वास्थ्य भी हैं जो उनके अधिकार की पृष्ठभूमि से संबंधित है। इसके अंतर्गत महिलाओं के उस अधिकार का उल्लेख है जिसके अंतर्गत उसे अपने बच्चों की संख्या नियंत्रित करने, यौनिक प्रहार से स्वतंत्रता तथा दैहिक हिंसा, आवांछित सामाजिक संबंध, वैश्यावृत्ति, बल प्रयोग यौन आदि तथा अवांछित चिकित्सीय हस्तक्षेप या शारीरिक अंगच्छेदन से अपनी रक्षा की स्वतंत्रता है। प्रस्तुत लेख प्रजनक अधिकार के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण के समाजशास्त्रीय विश्लेषण का एक प्रयास है।

**37. पुस्तक समीक्षा**—पुस्तक का नाम – बैकवर्ड कास्ट पालिटिक्स–ए स्टडी इन सोशियो– पालिटिकल मोबिलिटी, लेखिका – डा. ज्योत्सना शर्मा, रीडर समाजशास्त्र विभाग,एम.के.पी. कालेज, देहरादून, समीक्षक– डॉ. के.पी. सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर